दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 14 ▸ अंक : 7 ▸ गाजियाबाद, दिसंबर, 2018 ▸ मूल्य : 4 रुपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

भारत की सबसे महंगी फिल्म ने रिलीज से पहले ही...... P-8

पूरे भारतवर्ष में ईपीएफओ नोएडा को प्रथम स्थान मिला

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नोएडा। ईपीएफ नॉएडा को बड़े कार्यालय की श्रेणी में इपीएफ के स्थापना दिवस एक नवम्बर के मौके पर इस वर्ष प्रथम पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार श्रम मंत्री सन्तोष गंगवार ने गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम एन के सिंह को दिया। पुरस्कार में 5 लाख रुपये एवं ट्रॉफी प्रदान की गयी। नॉएडा ऑफिस ने केवाईसी अपडेट करने में, दावों के निबटान में, शिकायतों के निबटान में एवं अन्य सभी सेवाओं के क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

पिछले वर्ष भी नोएडा ऑफिस द्वितीय स्थान पर रहा था इस बार एक पायदान ऊपर छलांग लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम एन के सिंह ने कहा की यह सभी के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाया है।

ईपीएफओ नोएडा को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान मिला। श्रममंत्री सन्तोष गंगवार ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम गौतमबुद्ध नगर को पुरस्कार प्रदान किया।

कार्यालय के सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ में 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन उप्र ने भी अपना पूरा सहयोग इस ऑफिस को दिया है जिसकी वजह से आज हमें यह मुकाम हासिल हुआ है।

एमएसएमई को हर हाल में 45 दिन के अंदर भुगतान करना होगा

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यदि कोई भी एमएसएमई की सेवा लेता है या उनसे माल लेता है तो उसे एमएसएमई को हर हाल में 45 दिन के अंदर भुगतान करना होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि वे सभी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं और जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्राप्ति अथवा आभासी प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं हुआ है, वे निम्नलिखित

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
OUR STRENGTH • हमारी शक्ति
सत्यमेव जयते
Ministry of MSME, Govt. of India

❑ **केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यदि कोई भी एमएसएमई की सेवा लेता है या उनसे माल लेता है तो उसे एमएसएमई को हर हाल में 45 दिन के अंदर भुगतान करना होगा**

को दर्शाते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक छमाही रिटर्न प्रस्तु करेंगे:

(क) बकाया भुगतान की राशि और

(ख) विलंब के कारण।

यह अधिसूचना राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव द्वारा जारी की गई है।

उप श्रमायुक्त कार्यालय नोएडा को इंजीनियरिंग न्यूनतम वेतन की परिभाषा नहीं मालूम

सहायक श्रमायुक्त डॉ. हरिशचंद्र का कारनामा

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नोएडा। उप श्रमायुक्त कार्यालय नोएडा से एक कारखाना के मैनेजर ने पूछा की हमारी कम्पनी में री रोलिंग मिल का कार्य होता है कृपया यह स्पष्ट करें की हमारे ऊपर कौन सा न्यूनतम वेतन लागू होगा, इंजीनियरिंग या जनरल ताकि हम उस नियम का पालन कर सकें।

लेकिन विभाग ने बताने में असमर्थता जाहिर कर दी फिर काफी चक्कर विभाग के काटने के बाद विभाग में सूचना का अधिकार के तहत सूचना माँगी लेकिन विभाग ने 2 महीने बाद आज तक सूचना नहीं दी है। तथा इसे कानपुर हेड ऑफिस को रेफर कर दिया है। कानपुर श्रम विभाग के अधिकारी भी आज तक सूचना नहीं दे पाए हैं जबकि इसके बाद द्वितीय अपील भी कर दी गयी है तथा अब राज्य सूचना आयोग में जल्द ही अपील करने जा रहे हैं।

नोएडा के सहायक श्रमायुक्त डॉ. हरिशचंद्र ने यह सूचना देने में असमर्थता दिखाई यह कितने आश्चर्य की बात है की जब यही कारखाने में निरीक्षण करने जाते हैं तो किस आधार पर कारखाने का निरीक्षण करते हैं जब

❑ **जनपद के श्रमिकों मे नोएडा श्रम विभाग की नाकामी की वजह से बढ़ रहा है असन्तोष, दिन प्रतिदिन भयावह हो रही है स्थिति: आर पी सिंह चौहान (हिन्द मजदूर सभा)**

इनको कुछ मालूम ही नहीं है तो ये किस आधार पर श्रम कानून के मुकदमों का निबटारा करते हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है की श्रम विभाग में भ्रष्टाचर चरम पर है तथा ये लोग नोएडा में सिर्फ मोटी कमाई करने आते हैं तथा कारखाना मालिकों को प्रताड़ित करने के अलावा मजदूरों का भी उत्पीड़न करते हैं।

डॉ. हरिश्चन्द्र ने किस विषय में डॉक्टरी की है अब तो यह भी जाँच का विषय है। अब इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री से शिकायत करने की तैयारी हो रही है।

पिछले लगभग 6 महीने से विभाग में तमाम फाइल पेन्डिंग चल रही हैं जिनका निबटारा क्यों नहीं हो पा रहा है यह सोचनीय विषय है।

कंपनियों से ठगी करने वाला फर्जी एडीएफ पकड़ा

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नोएडा। सेक्टर–64 में कंपनियों के दस्तावेज की जांच करने के नाम पर लाखों रूपए की ठगी करने वाले एक फर्जी एडीएफ को पकड़ लिया। इस गैंग के सदस्य द्वारा अब तक विभिन्न कंपनियों से करोड़ों की ठगी करने का अनुमान है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सेक्टर–64 में आर एंड मोटर्स कंपनी है। एक व्यक्ति खुद को एडीएफ (असिस्टेंट डायरेक्अर ऑफ फैक्ट्रीज) बताते हुए कंपनी में आया। इसने कंपनी के तमाम दस्तावेजों की जांच कराने के लिए कहा। इससे कंपनी में मौजूद अधिकारियों ने उसे तमाम दस्तावेज दिखाने शुरू कर दिए। इस दौरान कंपनी के अधिकारी को उसकी गतिविधि पर शक हुआ। तो उन्होंने अपने सलाहकार श्रम कानून को सूचित किया। माथुर नोएडा के एडीएफ ब्रिजेश कुमार को जानते थे। उन्होंने ब्रिजेश कुमार को फोन कर उसके बारे में पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया। इसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। मगर कंपनी के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। मौके

❑ **गैंग के सदस्य अब तक विभिन्न कंपनियों से कर चुके ठगी**

❑ **पुलिस पूछताछ कर बाकी साथियों को तलाश कर रही**

पर पहुंची पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। आरोपी की पहचान ब्रिजेश निवासी लखनऊ के रूप में हुई है। उप निदेशक कारखाना ओ पी भारती ने बताया की शनिवार को उक्त कम्पनी के लीगल एडवाइजर आर सी माथुर एवं 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन उ.प्र. के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह का फोन आया की कंपनी

'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन उ प्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा की कम्पनी मालिकों को इस तरह के फर्जी लोगों से सतर्क रहना होगा तथा इस तरह के किसी भी अधिकारी के आने पर एसोसिएशन को तुरन्त सूचित करें हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। हमारा न 9818697406 है।

के अधिकारीयों को सहायक निदेशक कारखाना बृजेश कु सिंह उगाही के लिए धमका रहे हैं। जानकारी की गयी तो पता चला की यह क्षेत्र तो बृजेश का है ही नहीं यहाँ तो सहायक निद. शक कारखाना राम बहादुर तैनात हैं। इसने एक युवक को पहले भी धमक. ाकर यहाँ पर नौकरी पर लगवा दिया था। सहायक निदेशक कारखाना राम बहादुर ने कारखाने पहुँच कर पुलिस को बुला लिया और आरोपित को सौंप दिया। फेस थ्री कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी ने बताया की जाँच में आरोपित ने अपना नाम बृजेश पुत्र पंचशील मूल निवासी लखनऊ बताया। नोएडा में वह मामूरा में रहता है तथा पहले भी धारा 151 में बंद हो चुका है।

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/10/2018 To 31/03/2019

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7675.45
Semi Skilled	8443.00
Skilled	9457.49

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/08/2018 To 31/01/2019

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8975.63
Semi Skilled	9856.30
Skilled	10942.06

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9409.93
Semi Skilled	10350.93
Skilled	11291.92

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/10/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16962.00
Semi Skilled	15400.00
Un-Skilled	14000.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

परदेस की कमाई घर भेजने में भारतीय अव्वल

5 लाख करोड़ रुपए लगभग भेजे पिछले वर्ष भारतीयों ने विदेश से

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। विदेश से कमाई अपे घर भेजने के मामले में भारतीय अव्वल हैं। पिछले वर्ष दुनियाभर में काम कर रहे भारतीय नागरिकों ने 69 अरब डॉलर (करीब पांच लाख करोड़ रूपये) अपने देश में भेजे हैं। यह रकम पिछले वर्ष दुनियाभर में हुए रेमिटेंस (विदेश में काम कर रहे नागरिकों द्वारा कमाई अपने देश में भेजना) का 12 फीसद है। 2016 के मुकाबले पिछले वर्ष भारत में आने वाले रेमिटेंस की रकम लगभग आधा फीसद अधिक है।

कोटक महिंद्रा बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आने वाले रेमिटेंस का लगभग 59 फीसद चार राज्यों केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हिस्से में आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के मुताबिक इनमें केरल की 19 फीसद, महाराष्ट्र की 17, कर्नाटक में 15 और तमिलनाडु की आठ फीसद हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी के लिए सबसे ज्यादा लोग खाड़ी के देशों में जाते हैं। इनमें भी यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत में जाने वालों की संख्या सर्वाधिक रही है।

वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस में होने वाली वृद्धि साल 2017 में केवल पांच फीसद की रही है। आमतौर पर साल 2011–17 के दौरान भारत में रेमिटेंस की राशि 62 से 70 अरब डॉलर के बीच रही है। वैश्विक रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा विकासशील देशों के खाते में जाना स्वाभाविक है, क्योंकि विकसित देशों के मुकाबले उनके नागरिक रोजगार के लिए विदेश जाने को ज्यादा तैयार रहते हैं।

अब छह माह की नौकरी से ही मिलेगी ईएसआइ से इलाज की सुविधा

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआइ) ने नियमों में बदलाव किया है। इससे कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अब अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अब स्वास्थ्य बीमा धारक कर्मचारियों को सुपर स्पेशियलिट इलाज की सुविधा छह माह की नौकरी पूरी होने पर ही मिलने लगेगी, वहीं उनके आश्रितों को एक साल बाद यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। ईएसआइसी ने यह जानकारी हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर करके दी है। हलफनामे में कहा गया है कि ईएसआइसी कर्मचारियों के आश्रितों को एक साल बाद सुपर स्पेशियलिटी इलाज मुहैया कराई जाएगी।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS & PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

Social & Technical Audit

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- Payroll
- TDS
- ESI Act
- EPF Act
- Minimum Wages Act
- Bonus Act
- Payment of Gratuity Act
- Standing Order
- Workmen Health & Safety Policy
- First Aid Training & Certificates
- Factory Plan & Site Plan
- Factory Act-1948
- Shop & Establishment Act
- Social & Technical Audit

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818697406 / 9818036460

H.O. : BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad U.P.-201002. INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794
Mobile : 9818697406

B.O. : The Ithum IT Park, Suite #007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India

E-mail ID : - legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
03
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2018
P.

रक्तदान कर सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य का किया निर्वहन

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

गाजियाबाद। रक्तदान शिविर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमे सीमाशुल्क, कानकार, अल्बाटौस, सी एम ए सी जी एम, स्टार ट्रैक, सभी सीएचए बन्धु के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़–चढकर रक्तदान कर सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।

कस्टम विभाग के उपायुक्त चिन्तन रघुवंशी, सहायक आयुक्त डी के सिंह, अधीक्षकगण विनीत गोयल, मनोज अग्रवाल, प्रताप सिंह, निरीक्षक पाठक, श्रीमती दसपरीत कौर व सीएचए बन्धु नरेंद्र सिंह, कुलदीप, सीएफएस बंधु दिग्विजय सिंह आदि आदि व अन्य रक्तदान दाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन आईसीडी तिलपाटा दादरी पर किया गया।

इस अवसर पर 135 यूनिट रक्त एकत्र हुआ, रक्तदान दाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस शि. विर का आयोजन भारतीय सैनिकों व उनके परिवारजनों के लिए Armed Forces Transfusion Centre, Delhi Cantt (AFTC) की टीम द्वारा सूबेदार लक्ष्मण सिंह के कुशल नेतृत्व मे किया गया।

सभी रक्तदान दाताओं को अल्पाहार मेजूस, केला व बिस्कुट दिए गये साथ ही सभी रक्तदान करने वालों को सम्मान प्रतीक व मिल्क मग भी उपहार के रूप में प्रदान किए गए। AFTC की टीम के सभी सम्मानित सदस्यों को भी सम्मान प्रतीक, शाल, मिल्क मग, दो अन्य उपहार व भारत को जानो पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। शिविर में सहयोग करने के लिए AFTC, Concor, Impex Linkers, CMA CGM CFS, Albatross CFS व Clearfast Cargo को भी सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर शाखा की अध्यक्षा डाक्टर मधु पोद्दार, प्रभाकर जे पी, अनिता प्रभाकर, योगेश गुप्ता, अनिता गुप्ता, इंद्रा गर्ग, श्मधु जी डी मित्तल, पीयूष मित्तल, सतेंद्र सिंह वसुधीर दादू की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम संयोजक प्रवेश चंद्र गुप्ता, विनीत गोयल व मनोज कुमार अग्रवाल के अथक परिश्रम व प्रयास से कार्यक्रम का सफल आयोजन सम्पन्न हुआ। अध्यक्षा मधु पोद्दार व संयोजक प्रवेश चंद्र गुप्ता द्वारा सभी सदस्यों, सेना की टीम, सभी सहयोगियों व रक्तदान दाताओं का स्वागत व धन्यवाद किया गया। शिविर उपरांत सभी ने स्वरुचि भोजन का स्वाद लिया। मधु पोद्दर ने शिविर के सफल आयोजन के लिए समस्त टीम व सदस्यों का धन्यवाद व आभार जिनके सहयोग व समर्थन से यह सम्भव हो सका। विशेष रूप से विनीत गोयल व मनोज कुमार अग्रवाल का मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने इस आयोजन के लिए बहुत सहयोग व परिश्रम किया।

इस अवसर पर उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने भी 48वीं बार रक्तदान किया एवं कहा की लोगों को इस नेक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने चाहिए यह एक महान पुण्य कार्य है इसके माध्यम से आप कम से कम तीन लोगों की जान बचाते हैं। खून मात्र तीन महीने में फिर बन जाता है। इससे आप हृदय रोग, बी पी जैसी तमाम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सत्येन्द्र सिंह अभी तक 48 बार रक्तदान कर चुके हैं।

बढ़ता प्रदूषण

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

सदी शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या फिर गहरा चली है। नगरीय क्षेत्रों में यह खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगा है। नया तथ्य सामने आया है कि सींक वाली झाड़ू से सफाई करने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे लेकर काफी नाराज है और उसने उक्त झाड़ू के बजाय मशीनों से सफाई के निर्देश दिए हैं।

अभी तक नगरीय क्षेत्रों में सफाई के लिए सींक वाली झाड़ू का ही इस्तेमाल होता आया है। लेकिन, अब उसकी जगह मशीनें ले लेंगी। दूसरी समस्या है कूड़े को जलाने की। सफाईकर्मी अकसर कचरा इकट्ठा कर उसके जला देते हैं। इन सारी चीजों पर

> ❑ उचित होगा कि प्रदूषण को निर्धारित स्तर पर रोकने के लिए हर मोर्चे पर वास्तविक रूप से कार्य किया जाए

गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दरअसल, समस्या के समाधान के बजाय उससे भागने या उसे अनदेखा करने का याद यह शुतुरमुर्गी तरीका बहुत पुराना है। यह सही है कि प्रदूषण बढ़ाने के छोटे–छोटे कई कारण मिलकर बहुत बड़ा रूप धर लेते हैं और इन पर नियंत्रण से समस्या में कुछ कमी लाई जा सकती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस विषम स्थिति के लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है। जब कूड़ा जलाने पर सख्त प्रतिबंध है, आम लोगों पर इसे लेकर जुर्माना तक लगाया जाता है, ऐसे में सफाईकर्मियों पर कोई कार्रवाई न होना यह बताता है कि समस्या की जड़ कुछ और ही है। इसके वास्तविक रूप से अनुपालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उचित होगा कि प्रदूषण को निर्धारित स्तर तक पहुंचाने के लिए हर मोर्चे पर वास्तविक रूप से कार्य किया जाए। व्यापक पैमाने पर सघन जन–जागरण अभियान चलाकर बढ़ते प्रदूषण के खतरों के प्रति जनता को आगाह किए जाने की भी जरूरत है।

सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बिजली बिल में मिलेगी 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए बिजली बिल में एक रूपये प्रति यूनिट की छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 64 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने ओडीओपी उद्यमियों को शामिल करते हुए सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिजली में रियायत देने का निर्णय लिया है, ताकि वे बाजार में अपने उत्पादों की प्रतियोगिता में टिक सकें। इसके तहत तय हुआ है कि योजना के दायरे में सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमी लाए जाएंगे।

मशीनरी–प्लांट में 25 लाख रूपये तक निवेश होने पर उद्योग सूक्ष्म और 25 लाख रूपये से 5 करोड़ तक निवेश वाले लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तावित योजना के दायरे में आने वाले उद्यमियों को हर महीने समय से अपना

> ❑ 64 लाख उद्यमी होंगे लाभान्वित

पूरा बिल जमा करना होगा। इस बिल की रसीद को संबंधित पोर्टल पर अपलोड कना होगा। पॉवर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से इसका मिलान कराने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उद्यमियों के खातों में भेज दी जाएगी।

तीन साल में ग्रेच्युटी देने की तैयारी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। आम चुनावों से पहले ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे मसलों पर सरकार बड़े फैसले ले सकती है। अगले महीने चार दिसंबर को नवगठित ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की बैठक होनी है ऐसे में कई मुद्दे एजेडा में शामिल करने की कवायद तेज हो गई है।

1000 करोड़ का प्रावधान किया राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम ने, योजना में कर्ज की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि व सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह ने युवा सहकार उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 1000 करोड़ रूपये की 'युवा सहकार उद्यम सहयोग व नवाचार योजना', को लांच करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप योजना का रफ्तार देने और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत की गई है।

योजना को आकर्षक बनाने के लिए इसमें दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रूपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ प्रावधानों को सरल बना दिया गया है। इसके तहत ब्याज में दो फीसद की रियारती दी जाएगी। कर्ज लौटाने की अवधि दो साल बाद शुरू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अपना उद्योग जमाने में पूरी मदद मिलेगी। सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में कुल आठ लाख सहक. ारी संस्थाएं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने और युवाओं को इसमें लाने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। तीन साल पुरानी पंजीकरण वाली संस्थाओं की जगह एक साल पहले रजिस्टर्ड हुई सहकारी संस्थाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सहकारिता में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनसीडीसी की केंद्रीय मंत्री सिंह ने जमकर प्रशंसा भी की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्त क्षेत्र के लोग, दिव्यांग, महिलाएं और 115 आकांक्षी जिले के युवाओं को मिलेगा। इन्हें सामानय लाभार्थियों के मुकाबले कई लाभ भी मिल सकते हैं। सिंह ने बताया कि एनसीडीसी ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के वर्ष 2010–14 के कार्यकाल में 19,850 करोड़ रूपये के कर्ज वितरित किए थे, जबकि वर्तमानन राजग सरकार के वर्ष 2014–18 के कार्यकाल में कुल 63,702 करोड़ रूपये के कर्ज वितरित किए गए। यह पिछली सरकार के मुकाबले 220 फीसद अधिक है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
Editorial
04 P.
गाजियाबाद, दिसंबर, 2018

सम्पादकीय

राहत की पढ़ाई

सत्येन्द्र सिंह

शिक्षा व्यवस्था पर किए गए ज्यादातर अध्ययन यह बताते हैं कि स्कूली बच्चों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति अरुचि या उसे बोझ की तरह लेने का एक बड़ा कारण उनके कंधों पर जरूरत से ज्यादा भारी बस्ते का टंगा होना है। इसलिए अनेक शिक्षाविद लंबे समय से यह सुझाव देते रहे हैं कि स्कूली बच्चों पर किताबों के बोझ को कम किया जाना चाहिए। सरकारों की ओर से कई बार इस दिशा में कदम उठाने की बातें कही गईं। यों दिल्ली में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाता है। लेकिन देश भर में बस्ते के बोझ को कम करने के लिए अब तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आ सकी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देश पर अगर ठीक से अमल हुआ तो आने वाले समय में स्कूली बच्चों को भारी बस्ते के बोझ से बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परिपत्र के मुताबिक, पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को अब होमवर्क से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा, किताब-कापियों के उनके बस्ते का वजन अधिकतम डेढ़ किलो होगा। इसी तरह तीसरी से दसवीं कक्षा तक के बच्चों के बस्ते का अधिकतम वजन भी तय कर दिया गया है। दरअसल, इस तरह की पहलकदमी की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। निश्चित रूप से स्कूली बच्चों के कंधे पर यह बोझ कक्षा की किताबों और कॉपियों का होता है, लेकिन उसके भार तले उनका शरीर और मन-मस्तिष्क भी दबा होता है। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे स्कूली शिक्षा को अपनी जीवन-चर्या का सहज हिस्सा न मान कर, उसे एक जबरन निबाहने वाली ड्यूटी के तौर पर देखते हैं। खासतौर पर शुरूआती कक्षाओं में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र कई बार काफी कम होती है और उन्हें भी न केवल स्कूलों में अपनी कक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं, बल्कि आमतौर पर होमवर्क के रूप में घर में पढ़ाई पर समय देना पड़ता है। जिस उम्र में खेलना और अपने मन से कुछ नया करने-सीखने की कोशिश बच्चों की सामान्य इच्छा होती है उसमें उन्हें किताब-कॉपियों का भारी थैला उठाना पड़ता है। इसका सीधा असर उनकी सेहत और रचनात्मकता पर पड़ता है। बिना दिलचस्पी के की जाने वाली पढ़ाई का ही नतीजा यह होता है कि ज्यादातर बच्चों को किताबों में से कोई नई चीज सीखने के लिए अपेक्षया ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है। दरअसल, बोझ की तरह पढ़ने का सीधा असर सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं, जिनके मुताबिक पांचवीं या छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी या तीसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि बच्चों के भीतर सीखने की सहज प्रक्रिया पर किताबों से लेकर शिक्षण पद्धति का बोझ भारी पड़ता है। जबकि बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर तैयार किए गए विषय और पाठ्यक्रम ही कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों में सीखने के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं और इसके बाद पढ़ाई-लिखाई को लेकर वे सहज हो सकते हैं। बिना जरूरत की किताबों से भरे थैले और गैरजरूरी विषयों में बच्चों को उलझाना और उनके खेलने या अपनी तरह से कुछ करने की इच्छा को बाधित करके बेहतर नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते।

हमले और पीट-पीटकर मारने की घटनाएं क्या हमारी सभ्यता को दर्शाती हैं?

दिल्ली के द्वारका में नरभक्षी होने की अफवाह के चलते लोगों ने अफ्रीकी नागरिकों पर हमला कर दिया था। एक अन्य घटना में बेकाबू भीड़ ने पीट-पीटकर आटो ड्राइवर अविनाश कुमार की हत्या कर दी और दो अन्य को भी इतना पीटा कि वे अस्पताल में जिन्दगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इन पर बैट्री चोरी का आरोप था। हिंसा एवं अशांति की ऐसी घटनाएं देशभर में लगातार हो रही हैं। महावीर, बुद्ध, गांधी के अहिंसक देश में हिंसा का बढ़ना न केवल चिन्ता का विषय है बल्कि गंभीर सोचनीय स्थिति को दशार्ता है। सभ्य एवं शालीन समाज में किसी की भी हत्या या हिंसक व्यवहार किया जाना असहनीय है। इस तरह से भीड़तंत्र के द्वारा कानून को हाथ में लेकर किसी को भी पीट-पीटकर मार डालना अमानवीयता एवं क्रूरता की चरम पराकाष्ठा है। लेकिन प्रश्न यह है कि व्यक्ति हिंसक एवं क्रूर क्यों हो रहा है? सवाल यह भी है कि हमारे समाज में हिंसा की बढ़ रही घटनाओं को लेकर सजगता की इतनी कमी क्यों है? एक सभ्य एवं विकसित समाज में अनावश्यक हिंसा का बढ़ना विडम्बनापूर्ण है। ऐसे क्या कारण है जो हिंसा एवं अशांति की जमीं तैयार कर रहे हैं। देश में भीड़तंत्र हिंसक क्यों हो रहा है ? मनुष्य-मनुष्य के बीच संघर्ष, द्वेष एवं नफरत क्यों छिड़ गयी है ? कोई किसी को क्यों नहीं सह पा रहा है ? प्रतिक्षण मौत क्यों मंडराती दिखाई देती है ? ये ऐसे सवाल हैं जो नये बनते भारत के भाल पर काले धब्बे हैं। ये सवाल जिन्दगी की सारी दिशाओं से उठ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इंसान गढ़ने में कहां चूक हो रही है ?

दिल्ली के द्वारका में तंजानिया और नाइजीरियाई लोगों पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि इस तरह की अफवाह फैल गई थी कि उन्होंने 16 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसे मार डाला और उसे पका कर खा लिया, यह बेहद दुखद है। इससे देश की छवि को गहरा धक्का लगा है। पिछले वर्ष ग्रेटर नोएडा में भी स्थानीय लोगों ने अफ्रीकी छात्रों पर हमला कर दिया था। लोगों को संदेह था कि उन्होंने 17 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसे ड्रग्स दी थी, जिससे लड़के की मौत हो गई थी। सवाल तो यह है कि क्या लोगों का कानून-व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है? अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे सजा देने का काम पुलिस और न्याय व्यवस्था का है। भीड़ को कोई हक नहीं कि वह किसी की भी पीट-पीटकर हत्या कर दे। अगर सड़कों पर इन्साफ की अनुमति दे दी जाए तो पूरे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को सहन नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रकरण मॉब लिंचिंग की भयावह घटनाओं की याद दिलाता है जब अनेक राज्यों में अनेक मामलों में कई लोगों को भीड़ ने मार डाला था। लेकिन विडम्बनापूर्ण तो यह है कि इन घटनाओं के लपेटे में इस बार विदेशियों को लिया गया है? पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी छात्रों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। इस तरह की घटनाओं से देश की छवि पर आघात तो पहुंचता ही है, भारत के नस्लीय भेदभाव के विरोध और अश्वेतों को समान अधिकार और प्रतिष्ठा दिए जाने की वकालत को भी धुंधलाता है। क्या कारण है कि देश के भीतर के सामाजिक विभाजन एवं भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद उसे मिटा नहीं पाई। भले ही ऐसी वारदातें पुलिस की नजर में छोटी हों लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता एवं गौरवपूर्ण संस्कृति के लिये चिन्ताजनक है। तेजी से बढ़ता हिंसक दौर किसी एक प्रान्त का दर्द नहीं रहा। इसने हर भारतीय दिल एवं भारत की आत्मा को जख्मी बनाया है। अब इन हिंसक होती स्थितियों को रोकने के लिये प्रतीक्षा नहीं, प्रक्रिया आवश्यक है। यदि समाज में पनप रही इस हिंसा को और अधिक समय मिला तो हम हिंसक वारदातें सुनने और निर्दोष लोगों की लाशें गिनने के इतने आदी हो जायेंगे कि वहां से लौटना मुश्किल बन जायेगा। इस पनपती हिंसक मानसिकता के समाधान के लिये ठंडा खून और ठंडा विचार नहीं, क्रांतिकारी बदलाव के आग की तपन चाहिए।

देश में कई विसंगतिपूर्ण धाराएं बलशाली हो रही हैं, जिन्होंने जोड़ने की जगह तोड़ने को महिमामंडित किया है, प्रेम, आपसी भाईचारे और सौहार्द की जगह नफरत, द्वेष एवं विघटन को हवा दी। शायद यही वजह है कि भारत में अब भी लोग हर तरह के वर्ग और समुदाय के साथ घुल-मिलकर रहना सीख नहीं पाए हैं। उनके अचेतन में बिठा दिए गए पूर्वाग्रह समय-समय पर खतरनाक ढंग से सामने आते रहते हैं। दिल्ली में न सिर्फ विदेशियों बल्कि देश के पूर्वोत्तर से आने वाले लोगों के खिलाफ भी नफरत एवं हिंसा भड़क उठती है। हाल के वर्षों में उनको निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं घटी हैं। अन्य राज्यों में भी समय-समय पर प्रवासियों के खिलाफ हिंसा भड़क उठती है। एक आधुनिक और सभ्य समाज का लक्षण यह है कि वह अलग-अलग धाराओं से आने वाले लोगों और विचारों को खुले मन से स्वीकार करता है। विदेशियों का हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने या कारोबार के लिए आना इस बात का सबूत है कि वे हम पर भरोसा करते हैं। इस विश्वास का टूटना एक बड़ी चिन्ता का सबब है। तर्कहीन एवं अराजक हो रही भीड़ समाज का खतरनाक लक्षण है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काफी अफ्रीकी छात्र रहते हैं। इन विदेशियों पर नस्लभेदी टिप्पणियां की जाती हैं, उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। अफ्रीकियों पर हमलों की घटनाओं का असर केवल स्थानीय ही नहीं होता बल्कि इसका असर भारत-अफ्रीका सम्बन्धों एवं विदेश नीति पर पड़ता है। इससे कूटनीतिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका असर अफ्रीकी देशों में रह रहे भारतीय समुदाय पर भी पड़ सकता है। क्या सभ्य समाज में सोचने-समझने एवं विवेक की क्षमता खत्म हो रही है ? यदि ऐसा है तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि समाज असहिष्णुता एवं अराजकता की खतरनाक हद तक पहुंच चुका है।

राजनीति की छांव तले होने वाली भीड़तंत्र की वारदातें हिंसक रक्तक्रांति का कलंक देश के माथे पर लगा रहे हैं चाहे वह एंटी रोमियो स्क्वॉयड के नाम पर हो, विदेशियों पर अफवाहों के नाम पर हो या गौरक्षा के नाम पर। कहते हैं भीड़ पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। वह आजाद है, उसे चाहे जब भड़का कर हिंसक वारदात खड़ी की जा सकती हैं। उसे राजनीतिक संरक्षण ?मिला हुआ है जिसके कारण वह कहीं भी कानून को धत्ता बताते हुए मनमानी करती है। भीड़ इकट्ठी होती है, किसी को भी मार डालती है। जिस तरह से भीड़तंत्र का सिलसिला शुरू हुआ उससे तो लगता है कि एक दिन हम सब इसकी जद में होंगे। अक्सर हिंसा का प्रदर्शन ताकत दिखाने के लिए किया जाता है। अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों के पीछे भी यही कारण होता है। हिंसा एवं अराजकता की बढ़ती इन घटनाओं के लिये केकड़ावृत्ति की मानसिकता जिम्मेदार है। जब-जब जनता के निर्णय से राजनीतिक दल सत्ता से दूर हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही अराजक एवं हिंसक माहौल निर्मित किये हैं। आज राजनेता अपने स्वार्थों की चादर ताने खड़े हैं अपने आपको तेज धूप से बचाने के लिये या सत्ता के करीब पहुंचने के लिये। सबके सामने एक ही अहम सवाल आ खड़ा है कि ह्यजो हम नहीं कर सकते वो तुम कैसे करोगे?ह्ल लगता है इसी स्वार्थी सोच ने, आग्रही पकड़ ने, राजनीतिक स्वार्थ की मनोवृत्ति ने देश को हिंसा की आग में झोंक रखा है।

मॉब लिंचिंग या अफवाह पर हिंसक भीड़ के जुटने की घटनाओं ने राष्ट्र के गौरव को कुचला है। भीड़तंत्र भेड़तंत्र में बदलता जा रहा है। इस लिहाज से सरकार को अधिक चुस्त होना पड़ेगा। कुछ कठोर व्यवस्थाओं को स्थापित करना होगा, अगर कानून की रक्षा करने वाले लोग ही अपराधियों से हारने लगेंगे तो फिर देश के सामान्य नागरिकों का क्या होगा? देश बदल रहा है, हम इसे देख भी रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और भीड़ खुद फैसला करने लगी है। भारतीय समाज के लिए यह भयावह मुकाम है, नागरिकता खामोश है, यही इस समय की सबसे बड़ी गलती है। भावनाओं और नफरत के हथियारों को नुकीला बनाया जा रहा है ताकि लोग आपस में लड़ें। हिंसा ऐसी चिंनगारी है, जो निमित्त मिलते ही भड़क उठती है। इसके लिये सत्ता के करीबी और सत्ता के विरोधी हजारों तर्क देंगे, हजारों बातें करेंगे लेकिन यह दिशा ठीक नहीं है।

वैज्ञानिकों ने खोजी भारत में हॉग हिरन की दुर्लभ प्रजाति

भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में पाढ़ा (हॉग हिरन) की दुर्लभ उप-प्रजातियों में शामिल एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस की मौजूदगी का पता लगाया है। इससे पहले तक माना जाता रहा है कि हिरन की यह संकटग्रस्त प्रजाति मध्य थाईलैंड के पूर्वी हिस्से तक ही सिमटी हुई है। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुवांशिक अध्ययन में मणिपुर के केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में 100 पाढ़ा हिरनों की मौजूदगी का पता चला है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत-म्यांमार जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां पायी गई पाढ़ा की यह प्रजाति अनुवांशिक रूप से एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस से मिलती-जुलती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस के वितरण की पश्चिमी सीमा थाईलैंड न होकर मणिपुर है। विकास क्रम के लिहाज से अनुवांशिक विशिष्टता वाली पाढ़ा की इस आबादी की खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डॉ. एस.के. गुप्ता ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि "वन्यजीवों की पृथक एवं सीमित आबादी हमेशा चिंता का विषय रही है क्योंकि ऐसे में उनकी अनुवांशिक विविधता के लुप्त होने का खतरा रहता है। अनुवांशिक विविधता कम होने से बदलते पर्यावरण में जीवों की अनुकूलन क्षमता कम हो जाती है। इस संदर्भ में यह अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस के संरक्षण में मदद मिल सकती है।" अभी तक पाढ़ा की दो उप-प्रजातियों के पाये जाने की जानकारी है। ए.पी. पोर्सिनस (पश्चिमी नस्ल) के वितरण क्षेत्र में पाकिस्तान से लेकर हिमालय की पश्चिमी तराई में स्थित पंजाब के हिस्से, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, म्यांमार और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ग्रस्त मैदान शामिल हैं। वहीं, ए.पी. एनामिटिकस (पूर्वी नस्ल) के भारत एवं चीन समेत थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में पाये जाने की जानकारी मिलती है। हॉग हिरन या पाढ़ा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है।

भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की अनुसूची-1 के अंतर्गत पाढ़ा को संरक्षित किया गया है। पाढ़ा की एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस उप-प्रजाति अपने अधिकतर वितरण क्षेत्रों से सिमट रही है। वर्तमान में पाढ़ा की छोटी-सी बिखरी हुई आबादी कंबोडिया में पायी जाती है। कुछ समय पूर्व कंबोडिया में इस प्रजाति के हिरनों की केवल 250 संख्या के बारे में पता चला था। पाढ़ा हिरन परिवार से जुड़ा आदिम युग का स्तनपायी जीव है और प्लायोसीन तथा प्लाइस्टोसीन युग से इसकी मौजूदगी की जानकारी मिलती है। एक समय में यह पाकिस्तान से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता था। 20वीं सदी के आरंभ में पाढ़ा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फैला हुआ था। हाल के दशकों में आश्रय स्थलों के नष्ट होने के कारण पाढ़ा की आबादी में गिरावट हुई है। माना जा रहा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के अपने 35 आश्रय-स्थलों से पाढ़ा लुप्त हो चुका है। इस अध्यन से जुड़े शोधकर्ताओं में डॉ. गुप्ता के अलावा अजीत कुमार, संगीता एंगोम, भीम सिंह, मिर्जा गजनफारुल्लाह गाजी, चोंगपी तुबोई और सैय्यद ऐनुल हुसैन शामिल थे। यह अध्ययन शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन साइंस ऐंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, भारतीय वन्यजीव संस्थान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुदान पर आधारित है।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र

05 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, दिसंबर, 2018

मेट्रो फेज-2: जाम से बचने को डीएमआरसी ने दिए सुझाव

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

गाजियाबाद। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए मेट्रो फेज–2 में डीएमआरसी ने प्राधिकरण को सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में सभी स्टेशनों पर ड्राप लेन बनाने व तीन मेट्रो स्टेशनों पर छोटी पार्किंग विकसित करने के साथ ही जाम की समस्या से निपटने के लिए व्यस्त समय में बैरिकोडग के सुझाव शामिल हैं। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि हर मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक ड्राप लेन बनाई जाएगी। इस लेन में मेट्रो तक आने और जाने वाले यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। इस लेन में रुकना मना होगा, ताकि जाम की स्थिति न बने। डीएमआरसी ने तीन मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग बनाने की बात भी कही है। पहले इस रूट पर किसी भी स्टेशन के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि यह पार्किंग भी छोटी ही होंगी, जिनमें केवल 100 वाहनों तक की क्षमता होगी। डीएमआरसी के पास नया बस अड्डा मेट्रो, अर्थला व श्यामपार्क मेट्रो स्टेशन के पास छोटी पार्किंग

लायक जमीन है। जहां इन्हें विकसित कर मेट्रो का सफर करने वालों को थोड़ी राहत देने की कोशिश होगी। इसके अलावा डीएमआरसी व्यस्त समय में मेट्रो स्टेशनों के आसपास जाम से निपटने के लिए बैरिकोडग मुहैया कराएगा। जिससे व्यस्त समय में बड़ी संख्या में वाहनों के मेट्रो स्टेशन पहुंचने की स्थिति में एक अतिरिक्त लेन बनाकर यातायात को जारी रखा जाए।

जीडीए की मॉडल रोड होगी कलाकृतियों से गुलजार

गाजियाबाद। प्राधिकरण ने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से लेकर आईटीएस कट तक मॉडल रोड विकसित की है। इस रोड पर जीडीए शहर के कलाकारों को अपनी कलाकृतियों का नमूना दिखाने का मौका देगा, जिसके लिए उद्यान अनुभाग इस प्रस्ताव की तैयारी में जुटा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मॉडल रोड हिंडन एयरबेस से आइटीएस कट तक है, जिस पर विभिन्न कलाकृतियों का संगम दिखाई देगा। इसके लिए फिलहाल जीडीए कचरा महोत्सव में तैयार की गई कलाकृतियों को लगाएगा। जीडीए द्वारा सुंदरीकरण के तहत यहां काफी ग्रीनरी विक. सित की गई है। इस ग्रीनरी के बीच ही कलाकृतियां लगाई जाएंगी। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्कूल और कॉलेजों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वह स्वयंसेवी संस्थाओं एवं छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को यहां लगाएं, जिससे शहर अपने कलाकारों को हुनर को प्रदर्शित कर सकें। प्राधिकरण हर कलाकृति के लिए पोडियम बनाएगा जहां यह सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके अलावा कोई अन्य कलाकार यहां अपनी रचना को प्रदर्शित करना चाहे तो प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है। इस पूरी कवायद का उद्देश्य शहर में छुपी प्रतिभाओं के माध्यम से शहर का खुबसूरती को बढ़ाना है। कलाकृतियों के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए उद्यान अनुभाग तैयारी में जुटा है। शहर को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए चल रहे प्रयासों में यह भी मील का पत्थर साबित होगा।

–संतोष कुमार राय, जीडीए सचिव

उप श्रमायुक्त कार्यालय का एक और कारनामा, एक कारखाने के 12 लाख रुपए हड़पे

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नोएडा। उप श्रमायुक्त कार्यालय में यदि आपने गलती से भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम के तहत पैसे जमा कर दिए हैं तो आप भूल जाइये की आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। एक कारखाने वाले को इन लोगों ने डरा धमका कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम के तहत पैसे जमा करवा दिए जब कारखाने के अधिकारीयों ने अपने श्रम कानून सलाहकार से सलाह ली तब उनको मालूम चला की यह पैसे तो गलत जमा हो गए हैं क्योंकि उनके ऊपर तो यह अधिनियम लागू ही नहीं होता है। इस सम्बन्ध में जब श्रम विभाग के अधिकारीयों से बात की गयी तो कहना था की हम केवल लेना जानते हैं हमें देना नहीं आता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है की विभाग के अधिकारी कितने बेलगाम हो गए हैं एवं उनको किसी का भी कोई डर नहीं है। अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री से अपना सम्बन्ध बता कर एवं उनके गृहक्षेत्र के आसपास का बताकर लोगों को डरा रहे हैं की उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है वे सुपरमैन है। मुख्यमंत्री योगी को इस मामले में शिकायत की तैयारी की जा रही है। श्रम मन्त्री क्या कर रहे हैं यह सोचनीय है। एक तरफ जहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्योग लगाने के लिए परेशान है वहीं अधिकारी उनकी इस योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। यही हाल रहा तो यहाँ बड़े उद्योग तो बहुत दूर की बात है कुटीर उद्योग भी नहीं लग पाएंगे।

5 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी को मिलती है ग्रैच्युटी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। नौकरी करने वाले अधिकतर कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा ग्रैच्युटी फंउ के लिए कटता है। यह कर्मचारी की सैलरी का वह हिस्सा है जो उसे कंपनी में सर्विस के बदले मिलता है। इसे एक तह से बेनेफिट प्लान मामना जा सकता है तो नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी को मिलता है।

किसी भी कर्मचारी को ग्रैच्युटी पाने के लिए एक कंपनी में कम से कम 4 साल 10 महीने और 11 दिन काम करना जरूरी होता है। सरल भाषा में कहे तो एक जगह 5 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी को ग्रैच्युटी मिलती है। अगर आप ग्रैच्युटी बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो नीचे लिखे तरीके अपना सकते हैं–

खुद करें ग्रैच्युटी अमाउंट कैलकुलेट

आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लास्ट महीने की सैलरी की बेसिक सैलरी–नौकरी के साथ साल–15/26 का फॉर्मूला अपना सकते हैं।

कैलकुलेट करते समय यह बात ध्यान रखें कि अगर आपने किसी एक साल में 6 महीने से ज्यादा नौकरी की है तो उसे एक साल गिना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपने 5 साल 7 महीने कहीं काम किया है तो इसे 6 साल गिना जाएगा। वहीं अगर आपने 6 महीने से कम नौकरी की है तो उसे साल में नहीं गिना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपने 5 साल 5 महीने नौकरी की है तो उसे 5 साल गिना जाएगा।

ऑनलाइन चेक करें

अगर आप किसी जगह 5 सालों से ज्यादा नौकरी कर रहे हैं तो आप ग्रैच्युटी के हकदार हैं। आप अपनी ग्रैच्युटी का बैलेंस ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रैच्युटी आपकी लास्ट महीने की सैलरी की बेसिक पे, डीए और आपकी नौकरी की अवधि के आधार पर काउंट की जाती है।

कंपनी या नियोक्ता से पूछें

अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं तो आपकी ग्रैच्युटी मिलेगी। इसकी जानकारी आप कंपनी में एचआर से ले सकते हैं। एचआर के पास हर कर्मचारी का रिकॉर्ड रहता है। इसलिए आप इसकी जानकारी कंपनी से भी ले सकते हैं।

छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

गाजियाबाद। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की ओर से 24 नवंबर 2018 को रोटरी क्लब परिसर में विभिन्न विद्यालयों के आर्थिक रूप से पिछड़े 138 मेधावी छात्र छात्राओं को 423000 रुपयो की छात्रवृत्ति वितरित की गई। यह धनराशि समिति के सदस्यों, दानदाताओं एवं कारपोरेशन बैंक द्वारा अपनी सी एस आर योजना के तहत प्रदान की गई। समारोह के मुख्य अतिथि डीवीएस वर्मा जनरल मैनेजर कारपोरेशन बैंक थे।

समारोह की अध्यक्षता जेएल रैना ने की श्री वर्मा ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस धनराशि का उपयोग सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने में ही करें समिति के अध्यक्ष ने बच्चों को आश्वस्त किया कि उनकी शिक्षा में धन की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी समिति हमेशा उनकी सहायता को तत्पर है अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद करते हुए आशा की कि बैंक आने वाले समय में भी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ सचिव आर के गुप्ता ने समिति के द्वारा करें गए कार्यों के बारे में जानकारी दी समिति के शिक्षा प्रभारी एके गुप्ता ने कहा देश का भविष्य शिक्षित बच्चों पर आधारित है इसलिए समिति का प्रयास रहेगा कि उनकी शिक्षा में धन बाधा ना रहे मंच संचालन वीपी रस्तोगी ने करा। एल डी शर्मा, पीके वाषने, वीके भार्गव मुकेश खुराना केके सिहंल आदि उपस्थित रहे।

एससी-एसटी एक्ट के 13 मामले झूठे निकले

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विशेष सत्र न्यायालय ने नौ दिन में एससी–एसटी एक्ट के 14 मामलों में फैसला सुनाया है। इनमें से 13 मामले पूरी तरह से झूठे निकले हैं। कोर्ट में अभियोजन आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा, वहीं फरियादी ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। इससे आरोपित दोषमुक्त हो गए। इन लोगों ने लंबे समय तक एसी–एसटी एक्ट का दंश झेला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एससी–एसटी एक्ट से जुड़े केस सुनने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया है। विशेष न्यायाधीष बीपी शर्मा का स्थानांतरण कर रविंदर सिंह की इस न्यायालय में पदस्थापना की गई है। कोर्ट ने 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच 14 मामलों में फैसला सुनाया है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रामाचार पत्र
उद्योग–जगत
06 P.
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, दिसंबर, 2018

ईपीएफओ सक्रियः फर्जीवाड़े में शासकीय उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल

ज्यादा पेंशन के लालच में बनाए फर्जी दस्तावेज, अब खतरा!

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से ज्यादा पेंशन पाने के लालच में सैकड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स ने नियोक्ता संस्थानों से मिलकर फर्जी दस्तावेज बना लिए। इनमें कुछ कर्मचारी शासकीय उपक्रमों से भी ताल्लुक रखते हैं। ईपीएफओ अब तक पेंशन के 759 प्रकरण निरस्त कर चुका है और 6 हजार से ज्यादा मामले अभी स्क्रूटनी में हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा ईपीएफओ में बढ़ी हुई पेंश के प्रकरणों की छानबीन के दौरान हुआ।

विभाग से ज्यादा पेंशन पाने की खातिर कर्मचारियों ने नियोक्ता संस्थानों की सांठगांठ से ज्यादा वेतन के दस्तावेज बनवा लिए थे। ईपीएफओ ने जब छानबीन की तो कई प्रकरणों के झूठ का खुलासा हो गया। इस बीच ईपीएफओ ने सभी संस्थानों को चेता. वनी के साथ यह भी समझाइश दी है कि बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए किस तरह के कर्मचारी पात्र हैं और उनके आवेदनों में कौन से दस्तावेज संलग्न करना है।

फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ईपीएफओ अब ऐसे संस्थानों और पेंशनर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पूरे मध्यप्रदेश में ऐसे प्रकरणों की संख्या हजारों में निकने की आशंका है। केवल भोपाल कमिश्नररेट में ही 6 हजार आवेदन छानबीन में हैं। गलत दस्तावेज लगाने के कारण अब तक ईपीएफओ 759 प्रकरण निरस्त कर चुका है। ईपीएफओ ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि शासकीय उपक्रमों के कर्मचारियों ने भी फर्जी दस्तावेज लगा दिए। विभाग ने अपने नए निर्देशों में सभी संस्थानों से कहा है कि सभी नियोक्ता कर्मचारियों को जो भी दस्तावेज दें, उनका सत्यापन भी करें। इसके अलावा उसकी मूल प्रति भी अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे ईपीएफओ मिलान के लिए तलब कर सकता है। प्रपत्र '3ए' में हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता के वेतन से होने वाली कटौती का ब्यौरा होता है। बढ़ी संया में प्रपत्र '3ए' में भी गड़बड़ियां मिली हैं, ऐसे कर्मचारियों के संस्थानों और नियोक्ताओं से मूल दस्तावेज मांगे गए हैं।

दोषी लोगों पर होगी कार्रवाई: कमिश्नर

यह सही है कि छानबीन के दौरान गलत दस्तावेज वाले प्रकरण बड़ी संख्या में सामने आए हैं। 759 प्रकरण निरस्त भी हो चुके हैं, ऐसे मामलों में शोकाज नोटिस भी दिए जा रहे है। दोषी लोगों पर अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकती है। बढ़ी हुई पेंशन के मामले में अंतिम 12 माह के वेतन और सर्विस के आधार पर तय किए जाते हैं।

–संजय केसरी, क्षेत्रीय कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल

अन्य कमिश्नरेट में भी छानबीन : विभागीय सूत्रों का कहना है कि गलत पाए जाने पर ऐसे सभी प्रकरणों को अस्वीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य कमिश्नरेट में भी ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वास्तविक वेतन पर अंशनिधि वर्ष 2003 व 2009 में लिया था। पेंशन योजना की धारा 11(3) के तहत ऐसे कर्मचारी पात्र नहीं, फिर भी नियोक्ता ने ऐसे मामले ईपीएफओ के पास भेज दिए। यही वजह है कि फर्जीवाड़े की जांच शुरू की गई है।

ईपीएफओ ने ऐसे संस्थानों को शो. काज नोटिस थमा दिए हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित संस्थान और नियोक्ताओं पर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि यह गड़बड़ ईपीएफओ के पास पुराना रिकार्ड नहीं होने के कारण हुई। जो प्रकरण निरस्त हुए हैं उनमें कुछ मामले विधवा पेंशन के भी हैं।

उद्योग की लागत घटाने को बनेगा इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लान

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। माल की ढुलाई में तेजी लाने और कारोबारियों की परिचालन लागत घटाने के उद्देश्य से सरकार इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार कर रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इस प्लान में रेल, सड़क, हवाई और जलयान सभी क्षेत्र शामिल होंगे। यहां सीआइएलटी एक्सपो 2018 में उन्होंने कहा कि इस प्लान के तहत एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। व्यापार और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने में लॉजिटिक्स भी शामिल है।

इसमें सुधार होने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमे. रिका–चीन जैसे देशों के बीच कारोबारी तनाव बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। इससे भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए व्यापक कारोबारी अवसर पैदा हो रहे हैं। इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लान अहम है क्योंकि भारत के लिए लॉजिस्टिक्स लागत इसके सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के मुकाबले 14 फीसद है।

टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगले साल मिलेंगी बेशुमार नौकरियां

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। आइटी, ऑटोमोटिव, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण चार साल के अंतराल के बाद 2019 में बहाली की उम्मीद काफी मजबूत है। गुरुवार को जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के मुता. बिक बहाी को लेकर करीब 64 फीसद कंपनियों का रूख सकारात्मक है। 20 फीसद कंपनियों ने कहा कि अगले साल भी वे 2018 जितनी संख्या में ही बहाली करेंगी। कुछ ही कंपनियों ने 2019 में बहाली को लेकर नकारात्मक रूख का इजहार किया।

रिपोर्ट में कहा गया कि बहाली की संख्या हालांकि 2010–11 के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगी, फिर भी स्थिति पिछले 2–3 साल से बेहतर रहेगी। एचआर सॉल्यूशंस और एचआर तकनीक कंपनी पीपुलस्ट्रांग के सह–संस्थापक और सीईओ पंकज बंसल ने कहा कि यह देखना उत्साहवर्धक है कि तकनीक क्षेत्र में बेशुमार नौकरियों के द्वार फिर से खुल रहे हैं। बहाली की संभावना में बढ़ोतरी सिर्फ एक निश्चित आकार के संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न आकार और क्षेत्र की कंपनियों में भी यहीं स्थिति दिख रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक अगले वर्ष तकनीक क्षेत्र में बहाली फिर से काफी अधिक होने वाली है। इस क्षेत्र में डिजाइन और एनालिटिक्स में सर्वाधिक नौकरी मिलने की आशा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग जैसी विशेष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नौकरियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

डिजाइन, एनालिटिक्स में सर्वाधिक नौकरी मिलने की आशा, विभिन्न कारोबारी क्षेत्र की 64 फीसद कंपनियों में बहाली बढ़ने की आशा

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 भारतीय उद्योग परिसंघ, पीपुलस्ट्रांग, वीबॉक्स, यूएनडीपी, एआईसीटीई और एआईयू जैसे संस्थानों की संयुक्त पहल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में होने वाली सभी नई नियुक्तियों में 15–20 फीसद नियुक्ति महिला कर्मचारियों की होगी।

भारतीयों में बढ़ी रोजगार कुशलता, इंजीनियर सबसे ज्यादा योग्यः मुंबई

देश में रोजगार कुशल आबादी का हिस्सा बढ़कर 47 फीसद पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2–3 फीसद अंक अधिक है। साथ ही इंजी. नियर अधिक रोजगार कुशल वर्ग बनकर उभरे हैं।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच साल में देश की रोजगार कुशल आबादी का हिस्सा 14 फीसद अंक बढ़ा है, जो 2014 में 33 फीसद था।

फाइनल इयर इंजीनियरिंग ग्रैजुएट में से करीब 57 फीसद रोजगार कुशल पाए गए, जो पिछले साल के मुकाबले पांच फीसद अंक अधिक है।

मेट्रो के तीन स्टेशन पर ही पार्किंग मिलेगी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

गाजियाबाद। दिलशाद गार्ड से नया बस अड्डा तक मेट्रो शुरू होने की तैयारी शुरू हो गई है। मेट्रो शुरू होने से जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। डीएमआरसी ने आठ में से केवल तीन स्टेशनों पर ही छोटी पार्किंग बनाने की बात कही है। अन्य पांच स्टेशनों पर पार्किंग नहीं होगी। इन स्टेशनों पर यात्रियों के आने के बाद उनके वाहन वापस कर दिए जाएंगे। डीएमआरसी ने अर्थला,नया बस अड्डा और श्याम पार्क मेट्रो स्टेशनों पर ही छोटी पार्किंग बनाने की बात प्राधिकरण से कही है। पहले इस रूट पर किसी भी स्टेशन के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। इन स्टेशनों की पार्किंग पर केवल 100 वाहनों की क्षमता होगी।

डीएमआरसी के पास नया बस अड्डा मेट्रो, अर्थला व श्यामपार्क मेट्रो स्टेशन के पास छोटी पार्किंग लायक जमीन है। इन्हें विकसित कर मेट्रो का सफर करने वालों को थोड़ी राहत देने की कोशिश होगी। अन्य पांच स्टेशनों पर पार्किंग नहीं होगी।

जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि हर मेट्रो स्टेशन पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर एक 'ड्राप लेन बनाई जाएगी। इसमें मेट्रो तक आने और जाने वाले यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। इस लेन में वाहन ठहर नहीं सकेंगे जिससे जाम की स्थिति पैदा न हो सके। डीएमआरसी अति व्यस्त समय में मेट्रो स्टेशनों के आसपास जाम से निपटने के लिए बैरिकेडिंग मुहैया कराएगा।

कोट नहीं पहनने पर एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी की तीन डॉक्टर सस्पेंड

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी चंडीगढ़ का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण उन्होंने तीन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया।

न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार, हरियाणा सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि फार्मासिस्ट सविता, फिजियोथेरेपिस्ट दीपमाला तथा डाइटिशियन अपर्णा को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने ड्यूटी के दौरान चिकित्सकीय स्टाफ की पहचान ऐपरन नहीं डाला हुआ था, जिसके कारण मरीजों एवं अस्पताल स्टाफ में अंतर पता नहीं चल पा रहा था।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण तीनों को निलंबित करने के आदेश कर दिए हैं।

मैटरनिटी लीव के वेतन की भरपाई करेगी सरकार

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। 15,000 रुपये से ज्यादा हर महीने कमाने वाली महिलाओं को मिलने वाली मैटरनिटी लीव के 7 हफ्ते का वेतन केंद्र सरकार उनके एम्प्लॉयर को वापस करेगी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
राष्ट्रीय
07
P.
गाजियाबाद, दिसंबर, 2018

रेस्तरां ने सर्विस चार्ज लिया तो कर्मियों में बांटना जरूरी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। होटल या रेस्तरां यदि ग्राहकों से वसूले गए सर्विस चार्ज अपने कर्मचारियों में वितरित नहीं करते तो इस रकम पर उन्हें कर देना होगा। कर विभाग ने अधिकारियों को होटलों और रेस्तरां के अकाउंट्स की जांच कर यह पता लगाने के लिए कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सर्विस चार्ज की वसूली को नहीं दिखा रहे या कम दिखा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के इस निर्देश से पहे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि कुछ होटल और रेस्तरां ग्राहक. ों से अनिवार्य तौर पर सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, जो मंत्रालय के दिशा–निर्देश के विरूद्ध है। मंत्रालय ने यह भी आशंका जताई थी कि वसूले गए सर्विस चार्ज को कर्मचारियों में वितारित नहीं किया जा रहा है। सीबीडीटी ने अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि सर्विस चार्ज के नाम पर हो रही वसूली को न दिखाने या कम दिखाने जैसी गतिविधि

❑ अगर नहीं बांटा तो मानी जाएगी कंपनी की आय, देना होगा टैक्स

तो नहीं हो रही है। सीबीडीटी ने अपने निर्देश में कहा कि प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम–एक्सपेंडीचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में प्रदर्शित सर्विस चार्ज के ब्यौरे की गहन जांच होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि सर्विस चार्ज वसूली को होटल या रेस्तरां के कुल कारोबार के हिस्से के तौर पर पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है या नहीं। यदि सर्विस चार्ज वसूली को कर्मचारियों में वितरित नहीं करने का या इसे कम दिखाने या नहीं दिखाने का मामला सामने आता है, तो संबंधित होटल या रेस्तरां की इस वसूली पर कर लगाया जाना चाहिए। पिछले साल अप्रैल में उपभोक्ता मामों के मंत्रालय ने एक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ग्राहक द्वारा होटल या रेस्तरां को सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तह से वैकल्पिक है। ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल में साफ लिखा होना चाहिए कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है। बिल में सर्विस चार्ज का कॉलम खाली रखा जाए, ताकि ग्राहक बिल का भुगतान करने से पहले अपनी तरफ से उसमें राशि भर सके।

सीबीडीटी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उसे आगाह किया था कि कुछ होटल या रेस्तरां अब भी अपनी ओर से सर्विस चार्ज तय करते हैं और ग्राहकों को यह फैसा नहीं लेने देते कि वे स्वेच्छा से इसका भुगता करना चाहते हैं या नहीं। नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के पार्टनर सूरज नांगिया ने कहा कि ये दिशानिर्देश नियमों की अवहेलना करने वाले होटल या रेस्तरां मालिक की परेशानी बढ़ाएंगे क्योंकि इससे उनकी हरकतें सामने आएंगी। ऐसे कारदाताओं को अब या तो बिल पर से ऐसे शुल्क को हटा देना होगा या फिर इसके प्रभाव को कर्मचारियों के ऊपर डालना होगा।

सैमसंग ने मांगी माफी, कैंसर पीड़ितों को देगी एक करोड़

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। मोबाइल हैंडसेट मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग ने अपने सेमी–कंडक्टर निर्माण संयंत्रों में काम करते हुए कैंसर की चपेट में आए कर्मियों और उनके परिवारों से माफी मांग ली है। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने ऐसे सभी कर्मचारियों में से प्रत्येक को 15 करोड़ वोन (मौजूदा भाव पर करीब 96 लाख रूपये) के मुआवजे का भी एलान किया है। कई पीड़ित परिवारों ने हालांकि माफी को नाकाफी बताया है, लेकिन कहा है कि वे इसे भारी मन से स्वीकार लेंगे। कंपनी द्वारा माफी की इस याचना और मुआवजे की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों के साथ उसका एक दशक से चल रहा विवाद खत्म हो गया है। सैमसंग के को–प्रेसिडेंट किम की–नाम ने कहा, हम वैसे सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों से बेहद गंभीरता के साथ माफी मांगते हैं, जो कार्यस्थल पर गंभीर बीमारियों की चपेट में आए। हम अपने सेमी–कंडक्टर और एलसीडी निर्माण संयंत्रों में स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन में विफल साबित हुए हैं। वहीं, ऐसे कर्मचारियों के लिए अभियान चलाने वाले कई संगठनों का कहना है कि सैमसंग के सीमा–कंडक्टर और डिसप्ले संयंत्रों में काम करते हुए करीब 240 कर्मचारी कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार हुए। इनमें करीब 80 कर्मचारियों की मौत हो गई। कर्मचारियों और मृतकों के परिवारों के साथ हुए समझौते के तहत सैमसंग ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को 15 करोड़ वो का मुआवजा भुगता करेगी। इनमें कैंसर समेत 16 अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं। पीड़ित परिवारों में कई के मामले तो वर्ष 1,984 तक पुराने हैं।

फैसले का होगा व्यापक असर : मोबाइल हैंडसेट और कई अन्य टेक्नोलॉजी उपकरणों के डिसप्ले निर्माण में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिस तरह की तेजी आई है, उसे देखते हुए सैमसंग का यह फैसला अहम और ऐतिहासिक माना जा रहा है। दुनियाभर में दाम में मोर्चे पर दबाव झेल रही कई कंपनियां मोबाइल हैंडसेट की गुणवत्ता से समझौता करती हैं, जिसका असर कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर दिखता है। सैमसंग के इस फैसले से अन्य कंपनियों पर भी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा।

गाड़ी के कागजात न होने पर अब नहीं कटेगा चालान

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 में संशोधन किया है। इसको लेकर नोटीफिकेशन भी जारी कर चुका है। इस नोटीफिकेशन के बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसैंस, पॉल्यूशन सर्टीफिकेट, आर.सी., इंश्योरैंस के ओ. रिजनल कागज रखने की जरूरत नहीं होगी। अब आपके पास फोटो कॉपी या मोबाइ पर इलैक्ट्रॉनिक कॉपी है तो आप उसे दिखा सकते हैं और आपका

❑ फोटो कॉपी या मोबाइल पर इलैक्ट्रॉनिक कॉपी दिखाने की सुविधा

चालान नहीं कटेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यह नोटीफिकेशन 19 नवंबर को जारी किया गया है। इसके मुताबिक वर्दी में मौजूद कोई पुलिसकर्मी या अन्य अधिकारी गाड़ी से संबंधित कागजात मांगता है तो उसे इलैक्ट्रॉनिक कॉपी दिखा सकते हैं।

ईस्टर्न पेरीफेरल अंडरपास से दर्जनों एलईडी लाइट चोरी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

बागपत। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस–वे के अंडरपास में लगी दर्जनों एलईडी लाइट चोरी हो गई। राहगीरों ने पुलिस से शिकायत की है। एक्सप्रेस–वे का निर्माण शुरू होने के बाद से अभी तक चोर सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती दे रहे है। सप्ताह भर में चोरों ने बंथला–ढिकौली, बड़ागांव, सरफाबाद आदि मार्ग के अंडरपास से दर्जनों एलईडी लाइट चोरी कर लीं। इसकी वजह से दिन ढलते ही अंडरपास में अंधेरा छा जाता है। लूटपाट के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। राहगीर अशोक, संजय, माजिद, हामिद आदि का कहना है कि लाइटों की चोरी एक बार में नहीं बल्कि कई बार में की गई है।

इंस्पेक्टर शिव प्रकाश ने कहा कि गश्त बढ़ाते हुए चोरों की धरपकड़ की जाएगी। एक्सप्रेस–वे पर आए दिन चोरी होती है। सप्ताह में तीन चार बार मवीकलां इंटरचेंज के पास खड़े वाहनों से डीजल चोरी होने के साथ ही गत महीने चोरों ने दर्जनों सोलर पैनल चोरी कर लिए थे।

इतना ही नहीं अंडरपास में लगी बैट्रियां तक चोरी हो चुकी हैं। टोटियां चोरी होने के कारण अभी तक फव्वारे भी नहीं चल पा रहे। पूर्व में चोरी हुई सोलर पैनल भी अभी तक नहीं लगा गए। टोल प्लाजा तक में डकैती पड़ चुकी है।

अप्रैल से पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना नहीं होगा वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। अगले साल अप्रैल से वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र समय पर बनवाना और रिन्यू करवाना जरूरी होगा। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के आप एक अप्रैल से अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करा सकेंगे। सरकार ने बीमा कंपिनयों की दिक्कत और बढ़ते वाह प्रदूषण को देखते हुए पीयूसी प्रमाणपत्र के ब्योरे ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पीयूसी प्रमाणपत्र के ब्योरे सड़क मंत्रालय के 'वाहन' और 'सारथी' पोर्टलों पर एकीकृत किए जा रहा हैं। ज्यादातर राज्यों ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम और प्रक्रियाओं को दुरूस्त और ऑनलाइन कर सेंट्रल पोर्टल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया कर दी है। वे भी 31 मार्च तक सेंट्रल सिस्टम से जुड़ जाएंगे।

साथ रखने की नहीं होगी जरूरत : अगर आपने पीयूसी सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको आरसी और डीएल की तरह पीयूसी का कागजना दस्तावेज लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई आपसे इन कागजात की मांग करे तो आप उससे मोबाइल के जरिये 'वाहन' और 'सारथी' पोर्टल पर जाकर ब्योरा चेक करने को कहा सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल पर उसे दिखा सकते हैं।

सड़क मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आइटी एक्ट के तहत सभी डिजीटल दस्तावेज औरर सर्टिफिकेट उसी प्रकार मान्य और वैध हैं जिस प्रकार कागजी सर्टिफिकेट। इसलिए कोई पुलिसकर्मी या आरटीओ कागजी दस्तावेज के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अभी दिल्ली आदि महानगरों में तो ट्रैफिक पुलिस पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच करती है, परंतु छोटे नगरों और कस्बों में कोई इसकी परवाह नहीं करता। परंतु अप्रैल से कम से कम गाड़ी का बीमा कराने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी चालित सभी वाहनों के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया कदम

वैसे तो मोटरर वाहन नियम–1989 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी आदि के चलने वाले) वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। नए वाहन के साथ एक वर्ष तक वैध पीयूसी मिलता है। उसके बाद हर छह महीने में नया सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। लेकिन व्यवहार में इस कानून की पूरी तरह पालन नहीं होता। फलतः ज्यादातर वाहन चालक हानिकारक उत्सर्जन के साथ अपने वाहन दौड़ाते और वायुमंडल को प्रदूषित करते रहते है। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमा के लिए पीयूसी को अनिवार्य करने को कहा था।

बीमा कंपनियों ने बताई थी व्यावहा. रिक अड़चनें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़क मंत्रालय ने मई में बीमा नियामक इरडा से और इरडा ने बीमा कंपनियों से वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने का कहा था। लेकिन बीमा कंपनियों ने इसमें तकनीकी और व्यवहारिक अड़चनें बताई थी। इनमें एक अड़चन पीयूसी डेटा ऑनलाइन नहीं हो की थी, लेकिन सड़क मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसे अनिवार्य कर दिया।

कर्मचारियों को मुआवजे पर ब्याज घटना के दिन से देय

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। मजदूरों और वर्कमैन को बड़ी राहत देते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्कमैन कम्पनसेशन ऐक्ट के तहत दिये जाने वाले मुआवजे की रकम पर ब्याज घटना के दिन से देय होगा, न कि अवॉर्ड देने के लिए से। जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने मजदूरों के कल्याण की यह व्यवस्था एक फैसले में दी। इस मामले में नियोक्ता ने मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। उसने कर्मचारी की पत्नी को दिए गए मुआवजे को चुनौती दी थी। यह कर्मचारी काम के दौरान मर गया था। लेबर आयुक्त ने कर्मचारी को अवॉर्ड रकम पर 12 फीसदी ब्याज देने का आदेश दिया था। ब्याज की यह रकम अवॉर्ड देने के 45 दिन बाद शुरू होनी थी। कर्मचारी की ओर से यह मामला न तो हाईकोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसके पख में फैसला दे दिया। पीठ ने कहा कि कर्मचारी को मुआवजा अवॉर्ड पर दिया जाने वाला ब्याज घटना के दिन से चालू होगा। यह पहले से तय है कि मजदूर को काम के दौरान चोट लगने के दिन से भी मुआवजा मिलेगा।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

अमिताभ ने सफाईकर्मियों को गिफ्ट की मशीनें, कहा वादा निभाया

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन ने मेनहोल और सीवरों की हाथों से सफाई करने वाले सफाईकर्मियों की मदद के अपने वादे को पूरा करते हुए उनके लिए मशीनों का इंतजाम किया है. अमिताभ ने ट्वीट कर कहा, हाथों से सफाई करने वाले कर्मियों की अमानवीय स्थिति को देखते हुए मैंने उनके लिए 50 मशीनें खरीदने का वादा किया था. आज मैंने उस वादे को पूरा कर दिया है! सफाईकर्मियों को 25 छोटी अलग–अलग मशीनें और बीएमसी को एक बड़ी ट्रक मशीन उपहार में दी है. 24 नवंबर को एक पत्र लिखकर अमिताभ ने मैनुअल स्केवेंजर्स एसोसिएशन (एमएसए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से कहा था कि वह मेनहोल और सीवर नालों में सफाई के लिए उनमें उतरने वाले सफाईकर्मियों के लिए कुछ करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, मेरा योगदान सफाईकर्मियों को इस अमानवीय कार्य को करने से रोकने और उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा दिलाने के लिए है. अमिताभ ने सफाईकर्मियों के लिए मशीनें खरीदने के लिए 50 लाख रुपये देने का वादा किया था. अमिताभ ने ट्वीट कर कहा, मैं बीएमसी को एक बड़ी मशीन और सफाईकर्मियों को छोटी मशीनें दान कर रहा हूं. उन्होंने बीएमसी और एमएसए से मशीनों के सही प्रयोग की निरंतर रिपोर्ट देने का भी आग्रह किया है. अभिनेता किसानों की मदद के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.

अपने पैर कुल्हाड़ी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

दिवाली पर पटाखों के जरिये होने वाले घातक प्रदूषण के बारे में लोगों के तर्क हैरतअंगेज हैं। दिवाली और पटाखों का रिश्ता शाश्वत है, पर इसके आत्मघाी खतरों को नजरअंदाज करके पटाखों के पक्ष में तर्क गढ़ना अपने पैर कुल्हाड़ी मारने जैसा कृत्य है। किसी भी माध्यम से होने वाला प्रदूषण अंततः सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यह जानते हुए भी लोगों में इस दिवाली भी बेहद तेज ध्वनि और धुएं वाले पटाखों के प्रति न सिर्फ दीवानगी दिखी बल्कि कई लोग यह तर्क देते मिले कि एक दिन थोड़ा प्रदूषण बढ़ ही जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लोग न्यायालय, सरकार और मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाने में भी नहीं हिचकते। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

प्रदूषण के चलते लोग कैंसर, टीबी, अस्थमा, दमा और शारीरिक–मानसिक विकृतियों के शिकार हो रहे हैं। देश के चिकित्सा वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इन हाला के प्रति नागरिकों और नीति

- **लोगों को समझना होगा कि प्रदूषण न फैाने की नसीहत उनके परिवार और भावी पीढ़ियों के वजूद के लिए जरूरी**

निर्धारकों को लगातार आगाह कर रहे हैं। कुछ हिस्सों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए, पर दिवाली की रात डूबे लोग बेपरवाह दिखे। लोगों को अधिकतम उत्तेजना पैदा करने वाले पटाखे ही रास आते हैं। ये पटाखे वैसे तो हर किसी के लिए घातक होते हैं, पर बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिाएं इसका सर्वाधिक खामियाजा भुगतते हैं।

इस विषय पर कुछ वैसे ही व्यापक पैमाने पर जनजागरण अभियान की जरूरत है जैसा पोलियो उन्मूलन के लिए चलाया था। प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि प्रदूषण न फैलाने की नसीहत उनके अपने परिवार और भावी पीढ़ियों के वजूद की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है।

प्रियंका–निक के बाद ये जोड़ा करेगा जोधपुर के उम्मेद भवन में शादी

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी की तारीख नजदीक है. दोनों राजस्थान के जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन पैलेस में शादी करेंगे. प्रियंका की शादी को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है लेकिन खबर है कि वे 2 दिसंबर को निक जोनस संग 7 फेरे ले सकती हैं. यह एक भव्य शादी होगी जिसमें बॉलीवुड सितारे भी शरीक हो सकते हैं.

बात करें यदि प्रियंका–निक द्वारा शादी के लिए चुने गए वेडिंग प्लेस की तो यह बेहद खास है. इस जगह को फाइनल करने से पहले दोनों ही जोधपुर में घूमते देखे गए थे. प्रियंका–निक की शादी के बाद अब यह जगह एक अन्य शादी के लिए भी अभी से फाइनल हो चुकी है. जी हां, कुलभूषण खरबंदा की बेटी श्रुति खरबंदा इसी जगह पर अपने बॉयफ्रेंड संग 7 फेरे लेंगी. श्रुति अपने बॉयफ्रेंड रोहित नेवल संग पिछले काफी वक्त से रिलेशनशिप में हैं और 17 दिसंबर को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे. श्रुति के बॉयफ्रेंड के बारे में बता दें कि रोहित जो जीता वही सिकंदर, लगान, जोधा अकबर जैसी तमाम फिल्मों में सहयोगी भूमिकाएं निभा चुके हैं. श्रुति और रोहित ने इसी साल अगस्त में सगाई कर ली थी. दोनों की शादी का समारोह कुल 2 दिन का इवेंट होगा.

भारत की सबसे महंगी फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमा लिए इतने करोड़

मुंबई। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक लागत वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाने वाली रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और इस फिल्म को लेकर ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा।

एडवांस बुकिंग से अनुमानित 120 करोड़ रूपये

सेटेलाइट राइट्स से 110 करोड़ रूपये

तीन भाषाओं के डिजिटल राइट्स से 60 करोड़ रूपये

अन्य कमर्शियल अरेजमेंट्स से करीब 80 करोड़ रूपये

फिल्म 2.0 के तमिलनाडु और ओव. रसीज राइट्स अभी तक नहीं बेचे गए हैं स यहाँ सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के तहत फिल्म रिलीज की जायेगी ताकि मुनाफा बड़ा हो।

शंकर के निर्देशन में बनी रही रोबोटध्इंथिरन का ये सीक्वल पिछले दो साल साल से चर्चा में है। जिस इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड का वीएफएक्स इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ उसी पर करीब 75 मिलियन डॉलर का खर्च आया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म की कुल लागत अब 560 करोड़ रूपये तक पहुंच गई है। अपने बजट के कारण फिल्म 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। फिल्म को तमिल और हिंदी में रिलीज किया जाएगा और उसके बाद दस भाषाओं में भी ये फिल्म डब होगी। हिंदी 2.0 को करण जौहर और अनिल थडानी (रवीना टंडन के पति) की कंपनी रिलीज करेगी। फिल्म 2.0 को तैयार करने और उसे भव्यता देने के लिए दुनियाभर में करीब 3000 टेक्नीशियन ने दिन रात की मेहनत की है। फिल्म के पोस्टर से लेकर टीजर को ऐसा बनाने का दावा किया गया है, जो अब तक न देखा गया हो। भारी–भरकम स्पेशल इफेक्ट्स के कारण करीब 10 महीने लेट हो गई ये फिल्म 29 नवंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में रजनीक. ांत अपने पुराने वाले रोल में हैं जबकि अक्षय कुमार बड़े ही विचित्र गेट अप में विलेन का रोल निभाएंगे। साल 2010 में आई फिल्म रोबोट में ऐश्वर्या राय बच्चन थीं तो इस बार एमी जैक्सन फीमेल लीड में हैं। इस फिल्म के वीएफएक्स का काम एक अमेरिकी डिजिटल कंपनी को सौंपा गया था। कंपनी इससे पहले अपना काम पूरा कर पाती, उसकी माली हालत खराब हो गई और कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इस कारण 2.0 के निर्माता को 3डी और बाकी इफेक्ट्स का काम फिर से करवाना पड़ा।

द कपिल शर्मा शो का पहला टीजर आया सामने, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

उद्योग विहार (दिसंबर–2018)

नई दिल्ली। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के फैंस लम्बे वक्त से उनके टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहे थे, फैंस का यह इंतजार अब पूरा हो चुका है। जी हां कपिल शर्मा कॉमेडी शो का पहला टीजर आउट हो गया है। द कपिल शर्मा शो का टीजर बेहद ही शानदार है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस टीजर को सोनी टीवी ने ट्विटर पर जारी किया है। बता दें कि शो के रिलीज होने की डेट मेंशन नहीं की गई है पर ये जरूर लिखा है कि जल्द ही शो लोगों के बीच दस्तक देगा।

जारी हुए इस टीजर में समाज के हर तबके को जोड़ने की कोशिश की गई है। टीजर में ये भी दिखाया गया

है कि कैसे कपिल के शो ने भारत के कोने कोने में रहने वाले हर वर्ग के तनाव और दुख को कम करने में उनकी मदद करने में कारगार है। टीजर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जारी हुए टीजर में एक दिलचस्प लाइन है। वह लाइन है टीवी पर बस एक ही तो शो आता है जो इंडिया को एक साथ हंसाता है. . बल्कि अस्पताल में पड़ा एक मरीज भी इस शो को देखकर हंसे बिना रह नहीं पाता है जिसे देखकर नर्स भी मुस्कुरा उठती है और कहती है– लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसीन।

आपको बता दें कि चर्चित कॉमेडी प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो को पहले पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। पहले पार्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। मगर कपिल की हेल्थ और दूसरे कारणों की वजह से शो को बंद करना पड़ा। लेकिन कपिल एक फिर से टीवी की दुनिया में वापसी करने जा रहे हैं और सभी को हंसाने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि लंबे समय के बाद कपिल की वापसी क्या रंग लाएगी।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह